



एलओसी पर पाकिस्तान को दिया बड़ा जरूर

ऑपरेशन में 100 आतंकवादी मारे गए, भारत के सभी पायलट सुरक्षित

“
भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय सीमा में नहीं घुसने दिया, लेकिन इस समय इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कारबाही को नार गिराया।
लेपिटेनेंट जनरल राजीव घट्ट



नई दिल्ली। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ लॉन्च किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में भारतीय सेना ने रविवार को विस्तार से जाकरी दी। सेना ने बताया कि एलओसी पर जो पाकिस्तान ने घिरले दिनों जैसे गोलीबारी की, उसमें उनके 10 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि भारत के भी पायलट जवान शहीद हुए हैं। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। पाकिस्तान को आगाह करते हुए सेना ने कहा कि अगर पाकिस्तान अब भी सीजफार का उल्लंघन करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।

दीजोप्रेस जो लेपिटेनेट जनरल राजीव घट्ट है कहा, ‘कुछ हवाई क्षेत्रों पर हवा से बार-बार हमले हुए। सभी को विस्तार कर दिया गया। 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तो यहांने और छोटे हवाईयों से गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के लाभांग 35 से 40 जवान मारे गए हैं।’ इस तह भारत ने पाकिस्तान को इतना गहरा हो जाना चाहता है कि उसने पहुंचा रखा है। सेना ने कहा, ‘सात मई को घट्ट कर्वाई नहीं भूलने वाला। वहाँ, जब यह पूछा गया कि भारत ने ऑपरेशन के दैरान कितने पाकिस्तानी विमान मार गिराए, एयर मार्शल एके भारती ने कहा,

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। जाति आधारित जनगणना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए 70 साल पुराने जनगणना कानून में किसी तह के बदलाव की सरकार ने दिया पूरा ल्लौरा

जरूरत नहीं पढ़े। अधिकारियों ने बताया कि 1948 में बाय यह कानून, जिसे आखिरी बार 1994 में संशोधित किया गया था, केंद्र सरकार को जनगणना फॉर्म में शामिल किसी भी प्रकार की जातिकारी मार्गन की अनुमति देता है। इतिहास शास्त्रकाल में 1881 से 1971 तक की जनगणनाओं में सभी जातियों की गिनती की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद 1951 में पहली बार हुई जनगणना के दौरान, सरकार ने केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद 1951 में एयरपोर्टेज इंडियन एंड ट्रेस्टिंग कैरियर्स का डिजिटल मायम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय से कहा कि 300 करोड़ रुपये की यह

सरकार ने जातियों को अनुमति दी कि

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

और अधिकारियों को उन प्रश्नों को उत्तर देना है। उन्होंने कहा कि उन प्रश्नों का उत्तर देना की धारा 8 का बहाना देते हुए बताया कि जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

और अधिकारियों को उन प्रश्नों का उत्तर देना की धारा 8 का बहाना देते हुए बताया कि जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

और अधिकारियों को उन प्रश्नों का उत्तर देना की धारा 8 का बहाना देते हुए बताया कि जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए उसे निर्विशेष किया गया है।

जातिगत गणना : 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

यदि वे चाहें तो अपनी-अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से जातिकारी संरक्षित सेवकों का सरकार से नहीं है। अब, छह दशकों से अधिक समय बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में जाति आधारित गणना को शामिल करने का नियंत्रण किया है। अधिकारियों ने जनगणना अधिकारी एसें सभ

अपहरणकर्ता को पनाह देने का आरोपी को गिरफतार

बांगरमऊ। कोतवाली पुलिस ने लखनऊ मार्ग पर स्थित ग्राम आसत मोहिउद्दीन चौराहे से एक अनुसूचित जाति की युवती के अपहरणकर्ता को पनाह देने के आरोपी को गिरफतार कर दिया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर उसे अदालत भेज दिया।

</div

स्वतंत्र भारत

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

पाक की असलियत

पाकिस्तान ने पिर दिखा दिया है कि वह किसी रुम्ह या भरोसे के काबिल नहीं है। अमेरिका से दखल कर कर वह सीजफायर तक तो पहुंच गया लेकिन तीन घंटे के भीतर ही उसे तोड़कर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। भारत को पाक से खेल की आंशका थी। इसीलिए उसने साफ कह दिया था कि अगर पिर हमला हुआ तो हम निर्णयक जबाब देंगे। इसीलिए शनिवार रात आठ बजे के बाद हीने बाले हालों को उसने फैरेन जबाब देना शुरू भी कर दिया। इससे पहले चार दिनों में हमारी सेनाओं ने सभी तरफ से बांध कर पाक को घुटने टेकने को मजबूत कर दिया जबकि वह छल कपट का सहारा लेता रहा। यहां तक कि हवाई जहाज और ट्रेन सेवा जारी रखकर भारतीय हमलों को रोकने के लिए अपने ही नागरिकों को ढाल बनाता रहा। पिर भी पस्त होने पर दुनियाभर से बीच बचाव करने की गुहार लगाई। टकराव के देशों के बीच 'बिंग ब्रदर' की भूमिका में समझौता करने का शैक पाल चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाक के गिड़ियांगों पर समझौता तो करा दिया लेकिन उन्हें भी अंदर ज रहा होगा कि चढ़ घटों में ही यह बेमतलब हो जाएगा। शायद पाक को उम्मीद है कि अब जांग में वह आतंकियों को सफ़िय करके अपना बजन बढ़ा लेगा लेकिन भारत ने जिस तरह से अभी तक उसकी हर रणनीति को ध्वस्त किया है, ठीक उसी तरह इस बार भी होगा। अभी तक तो आतंकी लिपे ढांग से वार करते थे लेकिन आमने-सामने की जांग में वे कितने कामयाब हो पाएंगे, इसे लेकर कई शक नहीं होना चाहिए। दरअसल आतंक को संरक्षण और घुसपैट ही उसका पुगना हथियार है जिसे अब सारी दुनिया भी जानती है। इसीलिए जग छिल्जे के बाद तुर्कीए जैसे देशों को छोड़ दें तो किसी ने भी उसकी हिमायत नहीं की। जबकि भारत की नपी-तुली कार्रवाई को सभी ने देखा। देखा ही नहीं बल्कि उसका मजबूत आधार देखा और उसे मजबूत माना। पिर भी कूटनीतिक स्तर पर भारत ने सभी प्रभावशाली देशों के सामने अपनी स्थिति विस्तार के साथ स्पष्ट की। भारत अभी भी तनाव बढ़ाने के पश्च में नहीं है पर अगर फौज उसके ऊपर हमला करती है तो उसका स्टाईक जबाब देने में वह पीछे नहीं रहेगा। सीजफायर तोड़ने के बाद पाक की असलियत और कायदे से दुनिया के सामने आ गई है जबकि भारत की ओर से जबाबी कार्रवाई और सटीक ढंग से उसे सबक सिखाएंगी।

योगी पर भरोसा

केवल बातों से लोगों को आश्वस्त करने-भरमाने का चलन रजनीति के मौजूदा दौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकारों के कई मर्जियों व सियासी दलों के कई शीर्ष पदाधिकारियों से लेकर जिलात-हसील स्तर तक के नेता 'चांद सितारे तोड़ लाने' जैसे नामुकिन वादे ऐसी चाचानी में घोल कर पेश करते हैं कि जनता उन पर तुरंत भरोसा करती है। हालांकि कुछ समय बाद वह खुद को ठगा गया भी महसूत करती है। इसीलिए ऐसे आश्वासनों को जुमला कहा जाने लगा है। यूपी का यह सौंधाया है कि नेताओं में तेजी से बढ़ रहे 'जुमला कल्वर' के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'वर्क कल्वर' को बढ़ावा देते हुए जनता से सीधे जुड़ कर जनसमस्याओं के हल को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसके लिए लखनऊ और गोरखपुर में नियमित जनता दर्शन अलग ही नजीर बन गया है। ये जनता के लिए ऐसा अवसर बन गया है जिसमें समस्याओं के समाधान के रास्ते निश्चित रूप से संभव बन दिए जाते हैं। यह भरोसा प्रदेश के दूरदराज तक के लोगों में तो बढ़ा ही जा रहा है, अब अन्य प्रदेशों के फरियादी भी अपनी समस्याएं ले कर सीएम योगी के पास पहुंच रहे हैं। इन राज्यों में कांग्रेस शासित तेलंगाना और हिमाचल के निवासी तो हैं ही, उत्तराखण्ड, राजस्थान, एमपी जैसे बीजेपी शासित और उसके समर्थन से चल रहे बिहार के लोगों भी हैं। गत छह महीने के दैर्घ्यन दूसरे राज्यों के 65 से अधिक फरियादी यूपी के सीएम से अपनी समस्याओं के हल की गुहार लगा चुके हैं। इसके लिए योगी ने सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि समाधान की कार्रवाई के लिए फैसल कदम भी उठाए। ये समस्याएं संबंधित राज्य सरकारों हल कर सकती थीं लेकिन शायद उन्हें ये काम जरूरी नहीं लगा गया। सीएम योगी के प्रति यूपी से बाहर भी बढ़ते भरोसे के पीछे मुख्य कार्रवाई आम लोगों के साथ गहरा जुड़ाव, उनकी समस्याओं के हल को लेकर प्रतिबद्धता और समर्पण का उनका भाव है। योगी की 'प्रॉस यूपी' पहुंच उनकी व्यक्तित्व को अभिपूर्व नया आयाम देती है। अन्य राजनीतिज्ञ भी इसका अनुकरण करते तो तमाम गवर्नर्स की समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी।



पाकिस्तान ने तीन घंटे बाद तोड़ दिया युद्धविराम

युद्ध की घोषणा के बिना युद्धविराम हो गया?
खबरों के बीच सायरन न बजायें न्यूज चैनल-केंद्र

कई चैनलों ने तो पाक पर कब्जा भी कर लिया। उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो जायेगी प्रचंड गर्मी जितनी बार ये समाचार आया, पानी बरस गया!

विद्युत निजीकरण का निर्णय वापस लेने की मांग बिटिश कंपनियों के दलाल पैसा खा चुके हैं!

साइबर अपराधियों पर नियंत्रण करे सरकार-सपा

संगठित अपराध सरकारी नियंत्रण में ही होते हैं घुसपैठियों से पहला मोर्चा लेता है बीएसएफ पहलगाम आतंकी पता नहीं किधर से आये?



झूठ फैलाकर उन्माद को हवा देता 'गोदी मीडिया'

भा रत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच बिल्कुल स्वयं आतंक के मुंह तोड़ जवाब देने वाला देश है। परन्तु पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अंप्रेशन संदूक तक व उसके बाद युद्धविराम की घोषणा होने तक भारतीय मीडिया ने जिस गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया है उसके जितनी भरतीय विदेशी गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बनने की जाये वह कम है। यह जिम्मेदाराना जानकारी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान संदूक तक व उसके बाद युद्धविराम की घोषणा होने तक भारतीय मीडिया ने जिस गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया है उसके जितनी भरतीय विदेशी गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' पर सहमति बनने के बाद वह कम है। यह जिम्मेदाराना प्रसारण के लिए ये गोदी यूपी संघर्षविराम को लेकर देखा है।

में फरियाद लेकर जाने वाला नहीं बढ़ते देशों में 'तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम' अथवा 'पूर्ण संघर्षविराम' रूप से लेकर जिस गोदी यूपी संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'भारत और पाकिस्तान के बीच तल्काल और पूर्ण संघर्षविराम'

